भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 671

जिसका उत्तर 26 जून, 2019 को दिया जाना है।

5 आषाढ़, 1941 (शक)

डिजिटल इंडिया प्रोग्राम

671. श्री ए. राजा :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत आरंभ में देश भर में कितने राज्यों को कवर किया गया था;

(ग) देश भर में उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधियों का तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों और अब तक हासिल उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या विशेष रूप से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के समक्ष अनेक स्तरों पर बाधाएं आ रही हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) : इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार ने भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और एक ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के लिए 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम का कार्यान्वयन शुरू किया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 3 प्रमुख विजन क्षेत्रों पर केन्द्रित है अर्थात् प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना, मांग पर शासन और सेवाएं और नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य वृद्धि क्षेत्र के नौ स्तम्भों अर्थात् (i) ब्रॉडबैंड हाईवे (ii) मोबाइल कनेक्टिविटी का सार्वभौमिक अभिगम, (iii) सार्वजनिक इन्टरनेट अभिगम कार्यक्रम (iv) ई-शासन – प्रौद्योगिकी के जरिए शासन में सुधार, (v) ई- क्रांति-सेवाओ की इलेक्ट्रानिक प्रदायगी, (vi) सभी के लिए सूचना, (vii) इलेक्ट्रानिकी विनिर्माण- निबल शून्य आयात लक्ष्य, (viii) नौकरियों के लिए आईटी और (ix) शीघ्र फलदायी कार्यक्रम पर अधिक आवश्यक ज़ोर देना है।

(ख): डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल कर लिया गया है।

(ग) : डिजिटल इंडिया एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विविध परियोजनाओं को शामिल किया गया है। प्रत्येक परियोजना की अपनी बजटीय आवश्यकता है और तदनुसार परियोजना से संबंधी योजना को कार्यान्वयन मंत्रालय/विभागों द्वारा तैयार किया गया है और संबंधित मंत्रालयों /विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बजट संबंधी विवरण रखा गया है। तथापि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आबंटित और उपयोग किया गया बजट निम्नानुसार है :

वित्त वर्ष	**आबंटित बजट (करोड़ रु.में)**	**वास्तविक व्यय (करोड़ रु.में)**
2015-16	1550.80	1452.70
2016-17	1244.93	1217.65
2017-18	1413.63	1407.19
2018-19	3339.73	3328.57

(घ): डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अतंर्गत की गयी कुछ प्रमुख पहलों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :

- **भारत नेट** : भारतनेट ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टीविटी शुरू करने के लिए एक महत्वांकाक्षी पहल है। इस परियोजना को दूरसंचार विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। भारतनेट का उद्देश्य देशभर की सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों (जीपी) को जोड़ना और सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को 100 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। 1,28,870 ग्राम पंचायतों को जोड़ते हुए 337515 कि.मी ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई है 119513 ग्राम पंचायतें सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार हैं।
- **आधार:** आधार 12 अंक की बायोमेट्रिक और जनसांख्यकी आधारित पहचान उपलब्ध कराता है जो विशिष्ट, जीवन पर्यन्त और सत्यापन योग्य है। इसके अलावा आधार को सांविधिक समर्थन देने के लिए 'आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, लाभों और सेवाओं की लक्षित प्रदायगी) अधिनियम, 2016' को दिनांक 26 मार्च, 2016 को अधिसूचित किया गया। 123 करोड़ से अधिक निवासियों को नामांकित किया गया है।
- **सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी)** : सामान्य सेवा केंद्र, जो (जी2सी) सेवाएं प्रदान करने के लिए कयोस्क हैं, सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों (जीपी) में खोले जा रहे हैं। अब तक 3.65 लाख सामान्य सेवा केन्द्र सक्रिय हैं और ई-सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इनमें से 2.64 लाख ग्राम पंचायत स्तर पर हैं। अन्य सेवाओं के साथ-साथ सीएससी ग्रामीण नागरिकों के लिए बैंकिंग और वित्त संबंधित सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इन सीएससी के माध्यम से 300 से अधिक डिजिटल सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
- **मेघराज और सीएसपी :** डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भाग के रूप में भारत सरकार ने क्लाउड कम्प्यूटिंग के लाभों का दोहन और इसका सदुपयोग करने के प्रयोजन से "मेघराज" नाम से एक महत्वकांक्षी पहल शुरू की है। क्लाउड कम्प्यूटिंग को तेजी से अपनाने के लिए एमईआईटीवाई, भारत सरकार ने अलग-अलग नियोजन मॉडल अर्थात् सार्वजनिक क्लाउड, आभासी निजी क्लाउड और सरकारी समुदाय क्लाउड के अतंर्गत 13 क्लाउड सेवा प्रदाताओं के क्लाउड सेवा प्रदाताओं का पैनल बनाया है।
- **डिजिटल लॉकर** : डिजिटल लॉकर डिजिटल कोषों में दस्तावेज अपलोड करने के लिए जारीकर्ताओं के लिए कोषों के संग्रह और गेटवे सहित पारिप्रणाली उपलब्ध कराता है। डिजी लॉकर के अब तक 2.37 करोड़ पंजीकृत प्रयोक्ता हैं। 352 करोड़ प्रमाणित दस्तावेज जारी किए गए हैं। 126 जारीकर्ता और 36 अनुरोधकर्ता संगठनों को ऑनबोर्ड किया गया है।
- **ओपन सरकारी डेटा प्लेटफार्म**: ओपन सरकारी डेटा (ओजीडी) प्लेटफॉर्म भारत सरकार के ओपन डेटा पहल को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफार्म है। इसका लक्ष्य सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ विभिन्न परिप्रेक्ष्य में सरकारी डेटा के कई अन्य नवोदभव प्रयोगों के लिए मार्ग भी खोलना है। इस समय 148 मंत्रालयों/विभागों (85 केन्द्रीय और 63 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के विभाग) द्वारा प्रकाशित 4767 केटालॉग के अंर्तगत 294464 संसाधन इस प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं।
- **ई-ताल :** ई-ताल मिशन मोड परियोजनाओं सहित राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के ई-लेनदेन आंकड़ों के प्रसार के लिए एक वेब पोर्टल है। यह समय-समय पर वास्तविक समय के आधार पर वेब आधारित अनुप्रयोगों से लेनदेन आंकड़े प्राप्त करता है। जनवरी 2019 से 3702 सेवाओं के लिए 1454 करोड़ से अधिक लेनदेन दर्ज किए गए हैं।
- **सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम):** विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों/पीएसयू द्वारा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद को सुकर बनाने के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) को लागू किया गया है। जीईएम सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ाएगा। वर्तमान में, केंद्र सरकार और राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों द्वारा जीईएम का उपयोग किया जा रहा है। पोर्टल पर 242388 विक्रेता और सेवा प्रदाता पंजीकृत हैं। इसके अलावा अन्य सेवाएं पंजीकृत हैं जैसे परिवहन, स्कैनिंग / डिजिटाइजेशन, आईटी मैनपावर, एफएमएस इत्यादि। पोर्टल पर 1025319 उत्पाद और 11279+ सेवाएं उपलब्ध हैं।
- **ई-जिला मिशन मोड परियोजना :** ई-जिला मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जिला और उप जिला स्तर पर कार्यान्वित किया गया है। जिसका लाभ सभी नागरिकों को विभिन्न ई-सेवाओं जैसे कि प्रमाणपत्र (जन्म, जाति, मृत्यु,आय, और स्थानीय निवासी), पेंशन (वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा), शिकायत निवारण, निर्वाचन, ग्राहक न्यायालय, राजस्व न्यायायलय, भूमि रिकॉर्ड और विभिन्न विभागों जैसे कि वाणिज्यिक कर, कृषि पशुपालन और सहकारी, मजदूर रोजगार प्रशिक्षण और कौशल विकास इत्यादि की सेवाओं की सुपुर्दगी से से हुआ है। सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 721 जिलों में ई-जिला सेवाएं शुरू कर दी गई हैं।
- **जीवन प्रमाण**: जीवन प्रमाण के रूप में जानी जाने वाली पेंशनरों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट योजना के अंतर्गत जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटाइज करने की परिकल्पना की गई है। यह पेंशनभोगियों के लिए एक सक्षम बायोमेट्रीक डिजिटल सेवा है। इस पहल के साथ पेंशन भोगीयों को संवितरण एजेंसी या अधिप्रमाणन प्राधिकरण के समक्ष भौतिक रूप से मौजूद होने की आवश्यकता नही हैं। वर्ष 2014 से 2.58 करोड़ से अधिक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्रों पर कार्रवाई की गई है।
- **ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली (ओआरएस)/ई-अस्पताल**: ई-अस्पताल के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली (ओआरएस) में नए रोगियों द्वारा ऑनलाइन एपाइंटमेंट और पंजीकरण किया जाना, प्रयोगशाला की रिपोर्टों को देखना, रक्त की उपलब्धता की स्थिति की जांच करना और भुगतान गेटवे (पेगव) के साथ एकीकरण शामिल है। अब तक, ओआरएस के माध्यम से 205 अस्पतालों में 25.53 लाख ऑनलाइन एपाइंटमेंट किए गए हैं।
- **राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल** : राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) का विकास लाभार्थियों को छात्रवृत्ति की प्रक्रिया में अंत से अंत तक संवितरण के कार्यान्वयन के लिए एकल समाधान के तौर पर विकसित किया गया है। इस प्रक्रिया में छात्र का पंजीकरण, आवेदन,

- अनुमोदन और संवितरण शामिल है । 1.40 करोड़ से अधिक आवेदन प्रस्तुत किए गए गए हैं । 14 मंत्रालयों/विभागों से 60 पंजीकृत योजनाएं हैं।
- **एनसीओजी-जीआईएस अनुप्रयोग** : नेशनल सेंटर ऑफ जीयो-इंफॉर्मेटिक्स (एनसीओजी) परियोजना विभागों के लिए साझाकरण, सहयोग, स्थान आधारित विश्लेषकी और निर्णय सहायता प्रणाली के लिए विकसित एक जीआईसी प्लेटफॉर्म है। अब तक विभिन्न डोमेन में 230 अनुप्रयोग चल रहे हैं।
- **नए युग में शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्प (उमंग)**: आधार, डिजीलॉकर, पेगव, रैपिड आकलन प्रणाली (आरएएस) आदि के साथ एकीकृत मुख्य प्लेटफार्म के साथ प्रमुख सरकारी सेवाओं की प्रदायगी के लिए उमंग को एक ही मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। 73 विभाग और 18 राज्यों की लगभग 362 सेवाएं उमंग पर उपलब्ध हैं और दिन-प्रतिदिन इनकी संख्या बढ़ती जा रहा है।
- **माइगव** : माइगव भारत में सहभागितापूर्ण शासन के लिए अपनी तरह का पहला नागरिक भागीदारी मंच है। माइगव का लक्ष्य नागरिकों और सरकार के बीच वार्तालाप को सुविधाजनक बनाना है, जिससे नागरिकों को सरकार के करीब लाया जा सके और सरकार को इस मंच के माध्यम से नागरिकों के करीब लाया जा सके। इस समय माइगव के साथ 80 लाख से अधिक प्रयोक्ता पंजीकृत हैं, जो माइगव मंच पर होस्ट की गई विभिन्न गतिविधियों में भाग ले रहे हैं । 64 समूहों के अंर्तगत माइगव संबंधी गतिविधियां तैयार की गयी हैं जिसमें 813 टास्क, 800 चर्चाएं, 263 मत/सर्वेक्षण और 184 बातचीत शामिल हैं।
- **राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन (एनडीएलएम)/डिजिटल साक्षरता अभियान (डीआईएसएचए)**: भारत सरकार ने डिजिटल साक्षरता के लिए दो योजनाएं लागू की हैं, अर्थात् 10 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के साथ 'राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन' (एनडीएलएम) और प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को शामिल करते हुए 42.5 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के साथ डिजिटल साक्षरता अभियान (दिशा) । इन योजनाओं को देश भर में समवर्ती रूप से कार्यान्वित किया गया और कुल 53.67 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित और प्रमाणित किया गया है।
- **प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा)** : सरकार ने 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) को शामिल करते हुए ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता लाने के लिए फरवरी, 2017 में "प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा)" नामक एक नई योजना शुरू की है। 20 जून, 2019 की स्थिति के अनुसार कुल 2.11 करोड़ उम्मीदवारों को पीएमजी दिशा के अंर्तगत प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें 1.33 करोड़ अभियर्थियों से अधिक को अधिप्रमाणित किया गया है।

➢ **नौकरी के लिए आईटी** :

- भारत बीपीओ योजना के अंर्तगत 48,300 सीटों को अनुमोदित किया गया है तथा 20 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में 45,480 से अधिक बीपीओ/आईटीईएस की सीटें वितरित की गई हैं।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में बीपीओ के लिए 5000 सीटों को अनुमोदित किया गया है और पूर्वोत्तर के 6 राज्यों में 2485 सीटें आबंटित की गई हैं।

➢ **इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण**

- संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज (एम-सिप्स) : लगभग 52,083 करोड रुपए के प्रस्तावित निवेश के साथ 201 आवेदनो को अनुमोदित किया गया है। लगभग 5048 करो़ड रुपए के प्रस्तावित निवेश के साथ 20 आवेदनो को अनुमोदन हेतु मूल्यांकन समिति द्वारा सिफारिश की गयी है।
- इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) : देश भर के 15 राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) की स्थापना के लिए 1577 करोड़ रुपए की केन्द्रीय अनुदान सहायता सहित 3898 करोड़ रुपए के परियोजना के साथ 23 आवेदन (20 ग्रीनफील्ड ईएमसी और ब्राउनफील्ड ईएमसी में 3 आम सुविधा केंद्र) को अंतिम अनुमोदन दिया गया है।

(ड.): डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान समक्ष आने वाली प्राथमिक मुख्य चुनौतियां डिजिटल साक्षरता और डिजिटल कनेक्टीविटी हैं। सरकार ने पहले से ही 100 एमबीपीएस कनेक्टीविटी के साथ देश में सभी 250000 ग्राम पंचायतों को जोड़ने के उद्देश्य से भारत नेट परियोजना और 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को शामिल करने के उद्देश्य के साथ ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता का प्रसार करने के लिए ''प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा)'' के कार्यान्वयन के जरिए इन चुनौतियों से निपटने के लिए पहले से ही आवश्यक उपाय किए हैं।

******